(b) if so, the details of this representation by SCOPE: and

(c) reaction of Government to the representation?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI MANMOHAN SINGH): (a) to (c) Yes, Sir, a representation was received from the SCOPE which referred to the possible adverse effect of lowering of Customs Duties on ferrous and non-ferrous metals, on public sector enterprises and suggested a review of the extent of duty reduction. The Customs Duties on metals have been lowered taking into account the interests of both the manufacturers as well as the end-users. The present level of import duties is considered reasonable and there is no proposal to change them for the present.

प्रकल्पित कर योजना

1024. **श्री सतीश प्रधान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) देश में 1994-95 के वित्तीय वर्ष के दौरान प्रकल्पित कर योजना के अंतर्गत 1400 रूपये की राशि कर के रूप में भुगतान करने वाले कर-दाताआं की संख्या क्या हैं;

(ख) क्या यह सच हैं कि सरकार के उदार रवैये के कारण अन्य लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना के अधीन अधिकाधिक लोगों को शामिल करने के लिए सरकार क्या-क्या कदम उठाने का विचार रखती हैं?

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : (क) वित्त वर्ष 1994-95 के दौरान पूर्वानुमानित कर स्कीम के अन्तर्गत ऐसे 356322 मामले थे।

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115-ट के अनुसार किसी सामान या अन्य वस्तु के खुदरा व्यापार का कारोबार या भोजनालय चलाने के कारोबार या मोटर गाड़ी या मैक्सी-कैब या तिपहिया मोटरगाड़ी को चलाने या किराये पर देने या पट्टे पर देने के कारोबार में लगा व्यक्ति ही पूर्वानुमानित कर स्कीम का लाभ प्राप्त कर सकता हैं बशर्ते उक्त धारा में विनिर्दिष्ट दूसरी शर्तो को वह पूरा करता हो। धारा 115-ट में इस प्रकार विनिर्दिष्ट

न किया गया कोई भी दूसरा व्यक्ति इस स्कीम का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता।

(ग) पूर्वानुमानित कराधान की विद्यमान स्कीम के अधीन आने वाले व्यापारों की विभिन्न श्रेणियों के अधीन अधिक से अधिक व्यक्तियों को लाने के लिए व्यापक प्रचार अभियान चलाया जा रहा हैं। परन्तु इस स्कीम के अंतर्गत व्यापारियों की और अधिक श्रेणियों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

World Bank Study on Environmental Issues in Power Sector

1025. SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether World Bank has been permitted to launch a study of environmental issues in power sector in some States;

(b) if so, the details thereof with lames of States and the objectives of such a study;

(c) whether the effects of expansion of lower generation through coal on air, water and land have been identified luring such study; and

(d) if so, the details thereof and the remedial steps to *be* taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE V11NISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL): (a) to (d) Yes Sir. The Govemment have approved a study of environment issues in power sector to be carried out by the Wolrd Bank with Indian officials and experts playing an integral part in the w6rk. The study is to be conducted in Andhra Pradesh, Gujaratmd Bihar. The objectives of the study are to identify the main environmental effects related to the expansion of electricity generation. In particular the study will examine the impact of power sector expansion on air, land and water. On the basis of enviromental effects identified the study will suggest various options to mitigate these effects.